IJAER/Nov-Dec-2016/Volume-5/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

बढ़ती बेरोजगारी में औद्योगीकरण की भूमिका

Dr. Suman Gupta

Lecturer in Sociology

Govt College Kaladera ,Jaipur

सार

यह पेपर औद्योगीकरण के दौरान आर्थिक और रोजगार संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रस्तुत करता है भारत में आर्थिक परिवर्तन. हालाँकि भारत ने इसमें उल्लेखनीय प्रगति की है बदलती आर्थिक संरचना जिसमें सकल घरेलू उत्पाद में कृषि योगदान की हिस्सेदारी है इस पेपर का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका और साथ ही अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान का अध्ययन करना है। सीमित मात्रा में पूंजीगत संसाधनों के साथ, औद्योगिक क्षेत्र अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश उद्योग अधिक श्रम गहन हैं, यानी वे पूंजी की प्रति इकाई अधिक श्रम नियोजित करते हैं। लगभग 16% रोजगार इस क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। औद्योगिक विकास से भारी मात्रा में राजस्व उत्पन्न होता है। पूंजीगत वस्तुओं और बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना और विस्तार राजस्व सृजन में बहुत योगदान देते हैं। ये उद्योग रोजगार सृजन में योगदान करते हैं और इस प्रकार आय और राजस्व उत्पन्न करते हैं। औद्योगीकरण में वृद्धि से एक निश्चित क्षेत्र में बेरोजगारी और गरीबी की दर कम हो सकती है। औद्योगिक विकास से बड़े और छोटे दोनों प्रकार के व्यवसायों में अधिक नौकरियाँ पैदा होती हैं, जो उन लोगों के लिए अधिक अवसर प्रदान करती हैं जो अन्यथा बेरोजगार हो सकते हैं। पेपर में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास के बीच संबंधों पर भी जोर दिया गया है और सभी क्षेत्रों की समग्र उत्पादकता में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कुछ नीतिगत उपायों की सिफारिश की गई है।

सूचक शब्द: रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, श्रम गहन, औद्योगीकरण

परिचय

औद्योगीकरण विकासशील देशों में रोजगार वृद्धि और गरीबी में कमी का एक महत्वपूर्ण चालक है। कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण के प्रारंभिक चरण में, विशिष्ट विकासशील अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र में सेवा क्षेत्र की तुलना में अधिशेष श्रम को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है, जिसमें विशिष्ट कम आय वाले देश में अनौपचारिक सेवाओं का वर्चस्व होता है। हालाँकि अकुशल श्रमिकों को कृषि से विनिर्माण गतिविधियों में बेहतर वेतन वाली नौकरियों में ले जाना संभव है, लेकिन उन्हें औपचारिक सेवा क्षेत्र में ले जाना संभव नहीं है। बैंकिंग, बीमा, वित्त, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे औपचारिक सेवा क्षेत्रों की विशेषता अपेक्षाकृत कम रोजगार लोच है और इन क्षेत्रों में रोजगार के लिए कम से कम उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा की आवश्यकता होती है। अकुशल श्रमिकों को केवल अनौपचारिक क्षेत्र में ही रोजगार मिल सकता है

खुदरा व्यापार और वितरण, यात्री परिवहन और निर्माण जैसी सेवाएँ जहाँ मजदूरी और उत्पादकता अक्सर कम होती है। इसके विपरीत, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार, विशेष रूप से कपड़े और जूते जैसे पारंपरिक श्रम-गहन उद्योगों में, ज्यादातर नौकरी पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे देशों का औद्योगीकरण होता है, श्रमिकों को कम उत्पादकता वाली कृषि से विनिर्माण की ओर खींचा जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादकता में वृद्धि होती है और साथ ही कृषि में

प्राप्त निर्वाह आय की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र में बेहतर भुगतान वाली नौकरियों में कार्यरत श्रमिकों की हिस्सेदारी में वृद्धि। औद्योगीकरण से जुड़ा वेतन लाभ जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से को गरीबी से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है क्योंकि सामान्य रूप से कम आय वाले देश में श्रम ही गरीबों के स्वामित्व वाली एकमात्र संपत्ति है। इन प्रत्यक्ष प्रभावों के अतिरिक्त औद्योगीकरण भी हो सकता है

आर्थिक विकास के अर्थव्यवस्था-व्यापी सकारात्मक रोजगार प्रभाव के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण (लावोपा और स्ज्रिमाई 2013, वीस 2013)। जबकि आम तौर पर यह माना जाता है कि औद्योगीकरण संभावित रूप से रोजगार सृजन और गरीबी में कमी के लिए एक शक्तिशाली शक्ति हो सकता है, रोजगार की भयावहता और गरीबी का प्रभाव आर्थिक विकास के चरण के अनुसार भिन्न हो सकता है। आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में, देशों में श्रम-गहन उद्योगों में विशेषज्ञता होने की अधिक संभावना होती है, ताकि कम आय वाले देशों के लिए, औद्योगीकरण संभावित रूप से रोजगार सृजन पर एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव डाल सके और परिणामस्वरूप, उचित नीति वातावरण के तहत गरीबी में कमी आ सके। आय के उच्च स्तर पर, जैसे-जैसे देश श्रम-गहन उद्योगों से बाहर निकलकर पूंजी और प्रौद्योगिकी-गहन उद्योगों की ओर बढ़ने लगते हैं, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है

रोजगार और गरीबी में कमी पर औद्योगीकरण कमजोर होगा, हालांकि गरीबी में कमी पर औद्योगीकरण के मजबूत अप्रत्यक्ष प्रभाव हो सकते हैं, क्योंकि इससे प्राप्त लाभ पूंजी गहन उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश होता है, जिससे आर्थिक विकास और गरीबी में कमी आती है। यद्यपि कम आय वाले देशों को श्रम की कम लागत के कारण श्रम-केंद्रित विनिर्माण में स्वाभाविक लाभ होता है, हम देखते हैं कि अपेक्षाकृत कुछ विकासशील देशों को श्रम-केंद्रित विनिर्माण उत्पादों के उत्पादन और निर्यात में सफलता मिली है। यह ज्यादातर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में है, हम श्रम-प्रधान औद्योगीकरण में देशों की सफलता का निरीक्षण करें। जापान, उसके बाद कोरिया, सिंगापुर और ताइवान और हाल ही में चीन और वियतनाम से शुरू होने वाले इन दोनों क्षेत्रों के कई देश अपने आर्थिक विकास के आयात प्रतिस्थापन चरणों से निर्यात-उन्मुख विकास रणनीति में चले गए हैं जिसमें मजबूत विकास शामिल है प्रारंभिक वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र के श्रम प्रधान क्षेत्र में (रिडेल 1988, हैगार्ड 1996, क्रुएगर 1997, पर्किन्स 2013)। इन सभी देशों में, जैसे-जैसे उनकी अर्थव्यवस्थाएं विश्व बाजारों में अधिक निकटता से एकीकृत हुईं, आर्थिक विकास और संरचनात्मक परिवर्तन (अर्थात, कृषि से विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार का बदलाव) साथ-साथ चला, और अधिशेष श्रम को कम उत्पादक कृषि से अधिक उत्पादक विनिर्माण क्षेत्र में खींच लिया गया। श्रम-प्रधान औद्योगीकरण में कुछ देशों की सफलता और अन्य की नहीं, इसकी क्या व्याख्या है? एक ओर औद्योगीकरण और दूसरी ओर रोजगार और गरीबी के बीच संबंध विद्वानों के साहित्य के साथ-साथ नीतिगत बहसों में भी बहुत रुचि का विषय रहा है। इस पेपर में, हम सबसे पहले इस पर बहस से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करेंगे

औद्योगीकरण, रोजगार और गरीबी के बीच संबंध। फिर हम औद्योगीकरण और इसके रोजगार और गरीबी में कमी के प्रभावों के कुछ शैलीगत तथ्य प्रस्तुत करते हैं। अंतिम खंड नीतिगत निष्कर्ष निकालते हैं।

आर्थिक सुधार के दौरान भारत में आर्थिक और रोजगार संरचना में परिवर्तन 1986 में आर्थिक सुधार की शुरुआत के बाद से, भारत ने आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में बड़ी प्रगति हासिल की है। इसके अलावा, औद्योगीकरण ने पिछले दो दशकों में भारत की आर्थिक संरचना को गहराई से बदल दिया है (चित्र 1 देखें)। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 1990 में लगभग 32% से घटकर 2009 तक 17% हो गया है। सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 42% पर लगभग अपरिवर्तित रहा, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा तेजी से बढ़ गया। 25% से लगभग 42%। हालाँकि, कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का रोजगार योगदान अभी भी बहुत अधिक (54%) था, और 2009 में सकल घरेलू उत्पाद (17%) में इसके

योगदान के अनुपात से बहुत अधिक था (चित्र 2) (जीएसओ, 2010)। इससे पता चलता है कि पिछले दो दशकों में आर्थिक संरचना में बदलाव की तुलना में कृषि रोजगार संरचना में बदलाव बहुत धीमा रहा है। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र ने सुधार के दौरान रोजगार वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 1990 में केवल 16% था, लेकिन 2009 तक लगभग दोगुना, लगभग 26% हो गया। औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा मामूली वृद्धि के साथ लगभग 11% से लगभग 20% हो गया (चित्र 2)। 1990-2000 की अवधि में, लगभग 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% कृषि उद्योग सेवाएँ -4- सभी नव-सृजित नौकरियाँ सेवा क्षेत्र से थीं, जिसके लिए लेखांकन कुल नव-सृजित नौकरियों का लगभग तीन-चौथाई (जेनकिंस, 2004)। 1990-2009 की अवधि के दौरान, पिछले दो दशकों में क्षेत्र द्वारा रोजगार वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रोजगार वृद्धि दर औसतन लगभग 2.34% रही, जिसमें से औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह दर 4.8% प्रति वर्ष और 5.9% है। सेवा क्षेत्र (तालिका 1)। कृषि रोजगार वृद्धि दर की तुलना में, औद्योगिक रोजगार वृद्धि बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी सेवा क्षेत्र की तुलना में कम है। पिछले दो दशकों के दौरान दो असामान्य अवधियाँ ध्यान देने योग्य हैं। 1990 और 1991 के बीच, एसओई पुनर्गठन के कारण औद्योगिक क्षेत्र की रोजगार वृद्धि में तेजी से गिरावट आई, जिससे 800,000 नौकरियों का नुकसान हुआ, जो एसओई उद्यमों में श्रम बल के एक तिहाई के बराबर था (क्लम्प, 2007)। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि बढ़ी। दूसरी असामान्य अवधि 2000 से 2002 तक है जिसके दौरान औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार अचानक 2001 में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा लगभग 20% बढ़ गया, जिसका कारण 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80 था। % 90% 100% कृषि उद्योग सेवाएँ -5- 1999 के अंत में पहले उद्यम कानून की शुरूआत। उद्यमों, विशेष रूप से गैर-राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या, 2000 में 36,529 से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2002 में 57,545 उद्यमों तक पहुंच गई, 58% की वृद्धि,2 और इस कानून की बदौलत, इस कानून की शुरूआत (यूएनडीपी, 2003) के कारण लगभग दस लाख नौकरियां पैदा हुईं। कुल मिलाकर, पिछले दो दशकों में निजी क्षेत्र की भारी वृद्धि, विशेष रूप से अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र की रोजगार वृद्धि (डंग एट अल., 2004; जेनकिंस, 2004) के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि हमेशा उच्च रही है। रोजगार लचीलापन रोजगार संरचना परिवर्तनों की गति में असमानता को अच्छी तरह से समझाने में मदद करता है। यह इंगित करता है कि संबंधित क्षेत्र में एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत रोजगार में वृद्धि हुई है। तालिका 2 में हाल के दो दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार लोच की तुलना की गई है। 1986 और 2001 के बीच कृषि क्षेत्र की रोजगार लोच में तेजी से गिरावट आई, जबकि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

आर्थिक सुधार के दौरान भारत में आर्थिक और रोजगार संरचना में परिवर्तन

आर्थिक सुधार के दौरान भारत में आर्थिक और रोजगार संरचना में परिवर्तन 1986 में आर्थिक सुधार की शुरुआत के बाद से, भारत ने आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में बड़ी प्रगति हासिल की है। इसके अलावा, औद्योगीकरण ने पिछले दो दशकों में भारत की आर्थिक संरचना को गहराई से बदल दिया है (चित्र 1 देखें)। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 1990 में लगभग 32% से घटकर 2009 तक 17% हो गया है। सेवा क्षेत्र का हिस्सा लगभग 42% पर लगभग अपरिवर्तित रहा, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा तेजी से बढ़ गया। 25% से लगभग 42%। हालाँकि, कुल रोजगार में कृषि क्षेत्र का रोजगार योगदान अभी भी बहुत अधिक (54%) था, और 2009 में सकल घरेलू उत्पाद (17%) में इसके योगदान के अनुपात से बहुत अधिक था (चित्र 2) (जीएसओ, 2010)। इससे पता चलता है कि पिछले दो दशकों में आर्थिक संरचना में बदलाव की तुलना में कृषि रोजगार संरचना में बदलाव बहुत धीमा रहा है। दूसरी ओर, सेवा क्षेत्र ने सुधार के दौरान रोजगार वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 1990 में केवल 16% था, लेकिन 2009 तक लगभग दोगुना, लगभग 26% हो गया। औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा मामूली वृद्धि के साथ लगभग 11% से लगभग 20% हो गया (चित्र 2)। 1990-2000 की अवधि में, लगभग 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% कृषि उद्योग सेवाएँ -4- सभी नव-सृजित नौकरियाँ सेवा क्षेत्र से थीं, जिसके लिए लेखांकन कुल नव-सृजित नौकरियों का

लगभग तीन-चौथाई (जेनकिंस, 2004)। 1990-2009 की अवधि के दौरान, पिछले दो दशकों में क्षेत्र द्वारा रोजगार वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रोजगार वृद्धि दर औसतन लगभग 2.34% रही, जिसमें से औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह दर 4.8% प्रति वर्ष और 5.9% है। सेवा क्षेत्र (तालिका 1)। कृषि रोजगार वृद्धि दर की तुलना में, औद्योगिक रोजगार वृद्धि बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी सेवा क्षेत्र की तुलना में कम है। पिछले दो दशकों के दौरान दो असामान्य अवधियाँ ध्यान देने योग्य हैं। 1990 और 1991 के बीच, एसओई पुनर्गठन के कारण औद्योगिक क्षेत्र की रोजगार वृद्धि में तेजी से गिरावट आई, जिससे 800,000 नौकरियों का नुकसान हुआ, जो एसओई उद्यमों में श्रम बल के एक तिहाई के बराबर था (क्लम्प, 2007)। इसके विपरीत, इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि बढ़ी। दूसरी असामान्य अवधि 2000 से 2002 तक है जिसके दौरान औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार अचानक 2001 में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा लगभग 20% बढ़ गया, जिसका कारण 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80 था। % 90% 100% कृषि उद्योग सेवाएँ -5- 1999 के अंत में पहले उद्यम कानून की शुरूआत। उद्यमों, विशेष रूप से गैर-राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या, 2000 में 36,529 से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर 2002 में 57,545 उद्यमों तक पहुंच गई, 58% की वृद्धि,2 और इस कानून की बदौलत, इस कानून की शुरूआत (यूएनडीपी, 2003) के कारण लगभग दस लाख नौकरियां पैदा हुईं। कुल मिलाकर, पिछले दो दशकों में निजी क्षेत्र की भारी वृद्धि, विशेष रूप से अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र की रोजगार वृद्धि (डंग एट अल., 2004; जेनकिंस, 2004) के परिणामस्वरूप सेवा क्षेत्र के रोजगार में वृद्धि हमेशा उच्च रही है। रोजगार लचीलापन रोजगार संरचना परिवर्तनों की गति में असमानता को अच्छी तरह से समझाने में मदद करता है। यह इंगित करता है कि संबंधित क्षेत्र में एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धि के परिणामस्वरूप कितने प्रतिशत रोजगार में वृद्धि हुई है। तालिका 2 में हाल के दो दशकों में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार लोच की तुलना की गई है

चित्र 1: सेक्टर द्वारा सकल घरेलू उत्पाद का हिस्सा 1990-2009 (1994 स्थिर मूल्य पर)

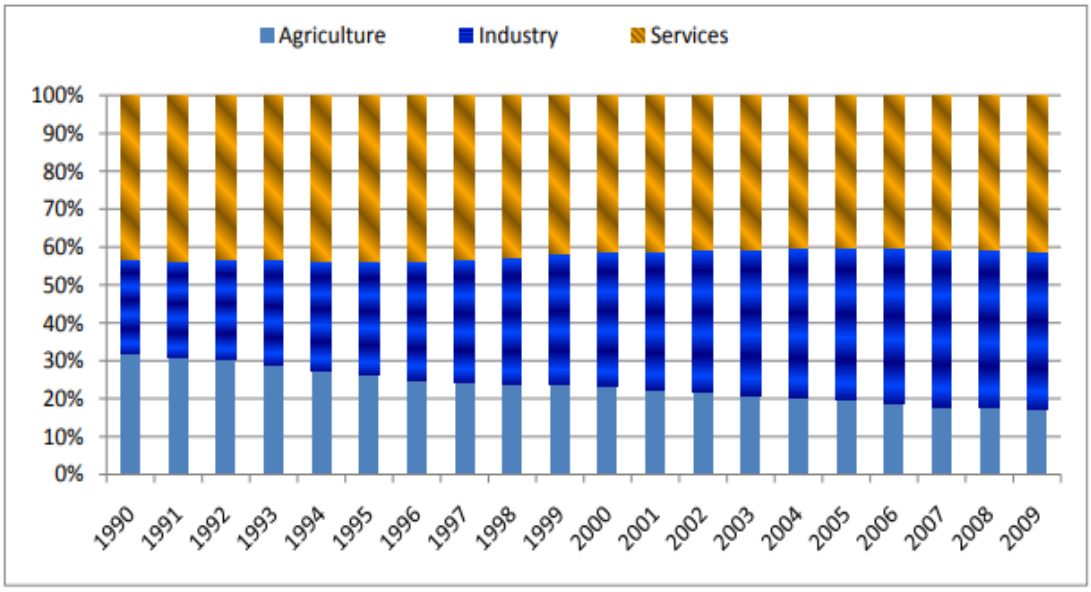

स्रोत: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=468&idmid=3&ItemID=9909

रोजगार सृजन में औद्योगिक क्षेत्र की भूमिका

कृषि श्रमिकों के आवागमन के लिए औद्योगिक क्षेत्र को व्यापक रूप से परिवर्तनकारी क्षेत्र माना जाता है कम कुशल से लेकर अधिक मूल्य वर्धित नौकरियों तक। ऐसा इसलिए है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक विकास हुआ है लोगों को

कृषि से बाहर निकालने, उन्हें गैर-कृषि गतिविधियों में स्थानांतरित करने का एक पैटर्न अपनाया गया विनिर्माण और सेवाएँ। अधिशेष श्रम को अवशोषित करने में (औद्योगिक क्षेत्र) की भूमिका का महत्व कृषि क्षेत्र की प्रगति कई विकसित देशों के विकास अनुभव से भी सिद्ध हो चुकी है देशों में और हाल ही में विभिन्न दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में।यह विनिर्माण को भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है, जहां कृषि का योगदान मामूली है सकल घरेलू उत्पाद, लेकिन रोजगार में असंगत रूप से बड़ी हिस्सेदारी के लिए जिम्मेदार है। लोगों की प्रचुर आपूर्ति कामकाजी आयु समूह में विनिर्माण विकास को बढ़ावा देने की क्षमता है। हालाँकि, इसमें से अधिकांश को अवशोषित करने के लिए श्रम शक्ति, मजबूत मानव पूंजी के निर्माण पर बड़ा जोर देने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण हैयह निश्चित मानते हुए परिवहन उपकरण, पेट्रोलियम और विद्युत मशीनरी जैसे विनिर्माण उद्योगों को इसकी आवश्यकता होती है विशेष प्रशिक्षण, जिसे केवल कुशल श्रम बल द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए विनिर्माण क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में गुणक प्रभाव पड़ता है अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर. विनिर्माण क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कच्चा माल और सेवाएँ प्राप्त करता है अर्थव्यवस्था और बदले में उन्हें तैयार उत्पादों की आपूर्ति करती है। इसलिए कच्चे से लेकर हर चीज की मांग बढ़ रही है मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए सामग्री। इसके प्रभाव क्षेत्र में सॉफ्टवेयर, स्वास्थ्य और परिवहन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जैसा एनएमपी में परिकल्पित विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है। हालाँकि, ऐसा होने से पहले, भारत के विनिर्माण और श्रम क्षेत्र में कुछ सुधार लाना महत्वपूर्ण है औद्योगीकरण1 विकास में रोजगार वृद्धि और गरीबी में कमी का एक महत्वपूर्ण चालक है देशों. कृषि अर्थव्यवस्था से आधुनिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण के प्रारंभिक चरण में, विशिष्ट विकासशील अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र में अधिशेष श्रम को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है सेवा क्षेत्र की तुलना में, जिसमें सामान्य रूप से कम आय वाले देश में अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व है सेवाएँ। जबकि अकुशल श्रमिकों को कृषि से बेहतर वेतन वाली नौकरियों में स्थानांतरित करना संभव है विनिर्माण गतिविधियाँ, उन्हें औपचारिक सेवा क्षेत्र में स्थानांतरित करना संभव नहीं है। औपचारिक सेवाएँ बैंकिंग, बीमा, वित्त, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र हैं अपेक्षाकृत कम रोजगार लोच की विशेषता है और इन क्षेत्रों में रोजगार की भी आवश्यकता है न्यूनतम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा। अकुशल श्रमिकों को केवल यहीं रोजगार मिल सकता है अनौपचारिक सेवाएं जैसे खुदरा व्यापार और वितरण, यात्री परिवहन और निर्माण जहां मजदूरी होती है और उत्पादकता प्रायः कम होती है।

मूल अध्ययन के लिए आरा मिलों और श्रमिकों का चयन

चौदह मध्यम से बड़े आकार की आरा मिलें, जो मुख्य रूप से दक्षिण-पश्चिम ईसा पूर्व में स्थित हैं, ने एक पूर्वव्यापी समूह अध्ययन में भाग लिया, जो 1987 और 1998 के बीच आयोजित किया गया था। मिलों का चयन क्लोरोफेनॉल के उपयोग के दीर्घकालिक इतिहास और बरकरार कार्मिक रिकॉर्ड की उपलब्धता के आधार पर किया गया था। समूह में कुल 28,794 श्रमिकों को नामांकित किया गया था, जो सभी बीसी आरा मिल श्रमिकों का लगभग 20 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। पात्र होने के लिए, एक कर्मचारी को 1 जनवरी, 1950 और 31 दिसंबर, 1998 के बीच कम से कम एक वर्ष के लिए एक अध्ययन मिल में नियोजित किया जाना था। समूह में 1950 से 1998 तक सभी समूह सदस्यों के कार्य इतिहास का डेटा शामिल है।

चूँकि 1980 में मंदी और आरा मिलों का बड़ा पुनर्गठन शुरू हुआ, इसलिए वर्ष 1979 को मंदी-पूर्व/पुनर्गठन "आधारभूत" वर्ष के रूप में चुना गया था। 1979 के दौरान समूह में नामांकित सभी श्रमिकों को इस आधारभूत उप-समूह में शामिल किया गया था। 1979 में एक अध्ययन आरा मिल में काम करने वाले 9,806 श्रमिकों में से 3,000 श्रमिकों का एक नमूना यादृच्छिक रूप से चुना गया था।

साक्षात्कारों का पता लगाना

साक्षात्कारकर्ताओं का पता लगाने के लिए 1979 उप-समूह को ब्रिटिश कोलंबिया लिंक्ड हेल्थ डेटाबेस (बीसीएलएचडीबी) से जोड़ा गया था। बीसीएलएचडीबी के माध्यम से हमें 6-अंकीय पोस्टल कोड के पहले 3-अंकों तक पहुंच प्राप्त हुई, जिससे हमें उस समुदाय की पहचान करने की अनुमति मिली जहां समूह के सदस्य रहते थे, ताकि हम स्थानीय सार्वजनिक सूचना स्रोतों के माध्यम से व्यक्तियों का पता लगा सकें। 1979 में एक अध्ययन मिल में कार्यरत 9,806 श्रमिकों को संभावित रूप से बीसीएलएचडीबी से जोड़ा गया था। लिंकेज दक्षता 94.7% थी, जिससे उप-समूह में 9,806 श्रमिकों में से 9,282 के लिए 3-अंकीय पोस्टल कोड प्राप्त हुए, जिनमें 3000 नमूना श्रमिकों में से 2,920 (97.3%) शामिल थे। 3,000 श्रमिकों के पूर्ण पते प्राप्त करने के लिए यूनियन पेंशन योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन डेटाबेस और टेलीफोन पुस्तकों (हाथ से) की खोज की गई। नमूने में 80 अनलिंक किए गए श्रमिकों के लिए, केवल नामों का उपयोग करके पते की खोज की गई थी।

साक्षात्कारों का संचालन करना

नवंबर 1997 और मार्च 1999 के बीच आमने-सामने साक्षात्कार आयोजित किए गए। प्रांत के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले विषयों का टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार किया गया। प्रश्नावली का एक संक्षिप्त संस्करण (एक घंटे की तुलना में लगभग 20 मिनट की आवश्यकता) टेलीफोन द्वारा प्रशासित किया गया था जब एक उत्तरदाता केवल एक संक्षिप्त साक्षात्कार आयोजित करने के लिए तैयार था या जब मृत और अक्षम साक्षात्कारकर्ताओं के लिए प्रॉक्सी साक्षात्कार आयोजित किए गए थे। हालाँकि, क्योंकि कार्य-संबंधी चर प्रश्नावली के संक्षिप्त संस्करण के साथ अपूर्ण रूप से निर्धारित किए गए थे, यहाँ वर्णित विश्लेषण में केवल प्रश्नावली के लंबे संस्करण का उपयोग किया गया था।

यंत्र

तकनीकी परिवर्तन, पुनर्गठन, बेरोजगारी, और स्वास्थ्य और कार्य पर साहित्य की गहन समीक्षा के बाद उपकरण विकसित किया गया था। प्रश्नावली को अंतिम रूप देने के लिए अनुभवी आरा मिल श्रमिकों के साथ दो फोकस समूह आयोजित किए गए; इसके बाद 29 सेवानिवृत्त आरा मिल श्रमिकों पर इसका प्रायोगिक परीक्षण किया गया। सामाजिक-जनसांख्यिकीय विशेषताओं को मापा गया। उनके श्रम बाजार अनुभव का पता लगाने के लिए, क्रॉस-सेक्टोरल और व्यावसायिक गतिशीलता का इतिहास और बेरोजगारी का इतिहास, एपिसोड की संख्या और अवधि द्वारा मापा गया, 1979 से साक्षात्कार के समय तक निर्धारित किया गया था। कार्य-स्तरीय कार्य विशेषताओं को मांग/नियंत्रण उपकरण [42] के संक्षिप्त संस्करण [40, 41] अतिरिक्त फ़ाइल देखें) का उपयोग करके मापा गया था। इस उपकरण में प्रश्न उत्तरदाता द्वारा रखे गए प्रत्येक पद के लिए निर्णय अक्षांश (नियंत्रण), मनोवैज्ञानिक और शारीरिक मांग, और सह-कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक के सामाजिक समर्थन को मापते हैं। अभी भी कार्यरत लोगों के लिए साक्षात्कार के समय नौकरी में मनोसामाजिक कार्य की स्थितियाँ निर्धारित की गईं।

निष्कर्ष

भविष्य में नीति सुधारों में बेहतर परिणामों के लिए परिवर्तन नीति निर्माताओं की अलग-अलग देशों की संरचनात्मक विशिष्टताओं और नीति इतिहास को ध्यान में रखते हुए नीतियों को तैयार करने की क्षमता पर निर्भर करता है, जबकि दोनों विचारधाराओं और आर्थिक सफलताओं के संचित साक्ष्यों पर आधारित है। अन्य देशों में विफलताएँ उद्यमशीलता प्रतिभाओं के पर्याप्त भंडार और एक अच्छी तरह से विकसित मानव पूंजी आधार के साथ अर्ध-औद्योगिक लोगों के लिए कारक और उत्पाद की कीमतें सही होना विनिर्माण विस्तार के माध्यम से श्रम अवशोषण प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नुस्खा हो सकता है। कम आय वाले देशों के लिए जो इन पूर्व शर्तों का आनंद नहीं लेते हैं, वहां अच्छी तरह से लक्षित और समयबद्ध प्रोत्साहन प्रदान करने के रूप में कुछ सरकारी हस्तक्षेप का मामला हो सकता है।

संदर्भ

1. पंचेको लोपेज़ पी. और थर्लवॉल, ए.पी. (2013) कलडोर के पहले विकास कानून की एक नई व्याख्या खुली विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ, केंट विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ़ इकोनॉमिक्स चर्चा पत्र, केपीई; 1312

2. स्ज़िरमाई, ए. (2012) विकासशील देशों में विकास के इंजन के रूप में औद्योगीकरण, 1950 2005, संरचनात्मक परिवर्तन और आर्थिक गतिशीलता 23, 406, 420

3. कलडोर, एन (1967) आर्थिक विकास में रणनीतिक कारक। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, इथाका। न्यूयॉर्क

4. डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, विश्व बैंक (2014)

5. विश्व बैंक (2014) सेनेगल देश प्रोफ़ाइल, 2014 उद्यम सर्वेक्षण

6. क्लूनीज़ रॉस, ए., फ़ोरेसिथ ओ और हक एम (2010) डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैकग्रा हिल, लंदन